भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3022
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्र

3022. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में स्थापित ई-सेवा केन्द्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) देश भर में उक्त ई-सेवा केन्द्रों द्वारा अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त ई-सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा स्थापित ऐसे ई-सेवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) छत्तीसगढ़ में स्थापित उक्त ई-सेवा केन्द्रों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के भाग के रूप में, ई-सेवा केंद्रों को वन स्टॉप सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है, जो अदालती मामलों/आदेशों/निर्णयों, न्यायालय से संबंधित मामलों की सुविधा और ई-फाइलिंग सेवाओं के बारे में निःशुल्क जानकारी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को लाभान्वित करते हैं, जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है या जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं । **उपाबंध-1** में दिए गए विवरण के अनुसार, अब तक जिला न्यायालयों में कुल 1072 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 27 ई-सेवा केंद्र देश भर में स्थापित किए गए हैं ।

ई-सेवा केंद्रों पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

- वाद स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरणों के बारे में पूछताछ का निपटारा करना ।
- प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना ।
- हार्ड कॉपी याचिकाओं की स्कैनिंग, ई-हस्ताक्षर जोड़ने, उन्हें सीआईएस पर अपलोड करने और फाइलिंग नंबर बनाने से लेकर याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करना ।
- ई-स्टाम्प पेपर/ई-भुगतान की ऑनलाइन खरीद में सहायता करना ।
- आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता करना ।
- एंड्रॉयड और आईओएस के लिए ई-न्यायालय के मोबाइल ऐप को प्रचारित करना और डाउनलोड करने में सहायता करना ।

- जेल में बंद रिश्तेदारों से मिलने के लिए ई-मुलाकात अपॉइंटमेंट की बुकिंग में सुविधा प्रदान करना ।
- अवकाश पर गए न्यायधीशों के बारे में प्रश्नों का समाधान करना ।
- लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करना ।
- वर्चुअल न्यायालय में ट्रैफ़िक चालान के निपटान की सुविधा प्रदान करना और ट्रैफ़िक चालान और अन्य छोटे अपराधों की ऑनलाइन कंपाउंडिंग करना ।
- वीडियो कॉन्फ्रेंस न्यायालय की सुनवाई की व्यवस्था और आयोजन की विधि की व्याख्या करना ।
- ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम से न्यायिक आदेशों/निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करना ।

इस प्रकार ई-सेवा केंद्रों की स्थापना से वर्चुअल सुनवाई, स्कैनिंग सुविधाएं और ई-न्यायालय सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा मिलती है, जिससे समग्र दक्षता बढ़ती है और इस प्रकार समय की बचत होती है, व्यापक यात्रा समाप्त होती है और खर्च कम होता है।

(घ) और (ङ) : ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के दूसरे चरण के अधीन, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को पायलट परियोजना के अधीन 2 ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 10.68 लाख रुपये जारी किए गए थे । हालांकि, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, अतिरिक्त ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 4.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है । 30.06.2024 तक, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला न्यायालयों में 23 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालय में 1 ई-सेवा केंद्र काम कर रहे हैं ।

*****

उपाबंध-1

न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †3022, जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

30.06.2024 को ई-सेवा केंद्रों के कार्यान्वयन की स्थिति				
क्र. सं.	**उच्च न्यायालय**	**क्या ई-सेवा केन्द्र उच्च न्यायालय में क्रियान्वित है?**	**क्या ई-सेवा केन्द्र जिला न्यायालयों में क्रियान्वित है?**	**जिला न्यायालयों में कार्यशील ई-सेवा केन्द्र**
1	इलाहाबाद	हां	हां	74
2	आंध्र प्रदेश	नहीं	नहीं	0
3	बॉम्बे	हां	हां	43
4	कलकत्ता	हां	हां	7
5	छत्तीसगढ़	हां	हां	23
6	दिल्ली	हां	हां	13
7	गौहाटी - अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	24
8	गौहाटी - असम	हां	हां	78
9	गौहाटी - मिजोरम	हां	हां	8
10	गौहाटी - नागालैंड	हां	हां	11
11	गुजरात	हां	हां	106
12	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	11
13	जम्मू-कश्मीर	हां	हां	9
14	झारखंड	हां	हां	24
15	कर्नाटक	हां	हां	24
16	केरल	हां	हां	162
17	मध्य प्रदेश	हां	हां	36
18	मद्रास	हां	हां	28
19	मणिपुर	हां	हां	15
20	मेघालय	हां	हां	15
21	उड़ीसा	हां	हां	126
22	पटना	हां	हां	37
23	पंजाब और हरियाणा	हां	हां	111
24	राजस्थान	हां	हां	1
25	सिक्किम	हां	हां	9
26	तेलंगाना	हां	हां	34
27	त्रिपुरा	हां	हां	15
28	उत्तराखंड	हां	हां	28
	क्रियान्वित किए गए	27	27	1072
	क्रियान्वित नहीं किए गए	1	1	

****